हिन्दी दैनिक

राष्ट्रीय स्वाभिमान

RNI No. : MAHHIN/2008/24084. www.rashtriyaswabhimaan.com

● वर्ष : 18 ● अंक : 126 ● मुंबई, बुधवार, 18 नवम्बर 2026 ● पृष्ठ : 4 ● मूल्य 1 रुपए

न्याय के मंदिर में ही न्याय की गुहार, 34 हजार कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

मुंबई। न्याय दिलाने की जिम्मेदारी निभाने वाली अदालतों में इन दिनों खुद न्याय की गुहार सुनाई दे रही है। समान काम के लिए समान वेतन और लंबे समय से लंबित वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर महाराष्ट्र की जिला एवं तहसील अदालतों के करीब 34 हजार कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। मंगलवार, 17 नवंबर से शुरू हुए इस आंदोलन ने राज्य की न्यायिक व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अदालतों में न्यायाधीश और अधिवक्ता तो पहुंच रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण मुकदमों की सुनवाई से लेकर फाइलों के रखरखाव, समन जारी करने, आदेशों की प्रतियां तैयार करने और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर व्यापक असर पड़ रहा है। वसई से बेलापुर और कल्याण से भिवंडी तक अदालत परिसरों में आंदोलन का माहौल है। कई मामलों में सुनवाई टालनी पड़ी, जबकि मुकदमों से जुड़े पक्षकारों और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

हड़ताल पर गए कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांग कोई नई या असाधारण नहीं है। वे लंबे समय से केवल उस वेतनमान और आर्थिक लाभ की मांग कर रहे हैं, जो समान प्रकृति का काम करने वाले उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को मिल रहा है। कर्मचारियों के अनुसार, बंबई उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की वेतनश्रेणी में वर्ष 2023 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप संशोधन किया गया था, लेकिन जिला और अधीनस्थ अदालतों में कार्यरत कर्मचारियों को अब तक इसका लाभ नहीं मिला। इस विसंगति को दूर करने के लिए बंबई उच्च न्यायालय ने 31 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। कर्मचारियों का आरोप है कि प्रस्ताव को भेजे हुए करीब 21 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक विधि एवं न्याय विभाग तथा वित्त विभाग की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। लगातार इंतजार और आश्वासनों के बावजूद समाधान नहीं निकलने से कर्मचारियों का धैर्य जवाब दे गया और आखिरकार उन्हें अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा।



कर्मचारी 1 जनवरी 2006 से चली आ रही वेतन विसंगति को दूर करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में काम करने वाले कर्मचारियों की जिम्मेदारियों और कार्यप्रणाली में काफी समानता है। इसके बावजूद वेतन और सुविधाओं में बड़ा अंतर बना हुआ है। कर्मचारियों का दावा है कि यह अंतर कई मामलों में 20 से 30 हजार रुपये तक पहुंच जाता है। उनका सवाल है कि जब अदालतों में न्यायिक प्रक्रिया को सुचारु रखने के लिए दोनों स्तरों पर कर्मचारी समान रूप से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं, तो वेतन निर्धारण में इतना अंतर क्यों रखा जा रहा है। कर्मचारियों का मानना है कि समान जिम्मेदारी के आधार पर समान वेतन देना प्रशासनिक न्याय और कर्मचारी हित, दोनों की दृष्टि से जरूरी है। इससे पहले कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 16 और 17 अक्टूबर को काली पट्टी बांधकर काम किया था। इस सांकेतिक विरोध के माध्यम से उन्होंने सरकार का ध्यान लंबित प्रस्ताव और वेतन विसंगति की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया था। उन्हें उम्मीद थी कि सरकार इस विरोध को गंभीरता से लेते हुए जल्द निर्णय करेगी, लेकिन कोई ठोस पहल सामने नहीं आई। इसके बाद महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर राज्यभर के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक संशोधित वेतनश्रेणी के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलती और उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं होता, तब तक आंदोलन वापस लेने का सवाल नहीं उठता। कर्मचारियों के हाथों में तख्तियां और बांहों पर काली पट्टियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि अब वे केवल आश्वासन से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। वसई न्यायालय में भी हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। यहां करीब 150 कर्मचारी आंदोलन में शामिल हुए। कर्मचारियों के काम पर नहीं पहुंचने से न्यायालय की नियमित गतिविधियां प्रभावित हुईं। न्यायाधीश और अधिवक्ता परिसर में मौजूद रहे, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ी कई जरूरी औपचारिकताएं कर्मचारियों के अभाव में आगे नहीं बढ़ सकीं। फाइलों को संबंधित विभागों तक पहुंचाने, दस्तावेजों के प्रबंधन और सुनवाई से जुड़ी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में बाधा आई। इसके चलते कई मामलों में निर्धारित समय पर प्रक्रिया पूरी करना मुश्किल हो गया। अदालत में आने वाले पक्षकारों को भी यह समझने में परेशानी हुई कि उनकी सुनवाई और अन्य काम कब तक सामान्य हो पाएंगे। कल्याण न्यायालय में भी कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। यहां करीब 180 कर्मचारी हड़ताल के पहले दिन न्यायालय परिसर के बाहर जुटे। ठाणे जिला न्यायालयीन कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष माणिक भालेराव ने कहा कि जब तक सरकार संशोधित वेतनश्रेणी के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देती, तब तक हड़ताल समाप्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कर्मचारियों की मांगों को लंबे समय से लंबित बताते हुए सरकार से तत्काल निर्णय लेने की अपेक्षा जताई। हड़ताल का असर न्यायिक कामकाज पर भी साफ दिखाई दिया। निर्धारित सुनवाई वाले कई मामलों को अगली तारीख देनी पड़ी। इससे उन पक्षकारों को परेशानी हुई, जो दूर-दराज के क्षेत्रों से अपने मुकदमों की सुनवाई के लिए अदालत पहुंचे थे। उन्हें यात्रा और समय खर्च करने के बाद बिना सुनवाई के लौटना पड़ा। कल्याण जिला न्यायालय वकील संघ ने भी कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन दिया। कुछ अधिवक्ता कर्मचारियों के साथ धरने में शामिल हुए और मांगों के समाधान के लिए सरकार से हस्तक्षेप करने की अपील की।

भिवंडी जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय में भी आंदोलन का प्रभाव व्यापक रहा। यहां 125 से अधिक कर्मचारी न्यायालय परिसर में धरने पर बैठे। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण करीब 1,675 मामलों की सुनवाई और उनसे जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर संकट मंडराने लगा है। अदालतों में मुकदमों की सुनवाई केवल न्यायाधीश और वकीलों की उपस्थिति से पूरी नहीं होती, बल्कि इसके पीछे कर्मचारियों की एक बड़ी टीम लगातार काम करती है। फाइलों का संधारण, तारीखों का रिकॉर्ड, नोटिस और समन की प्रक्रिया, आदेशों की प्रतियां तैयार करना तथा विभिन्न दस्तावेजों को संबंधित पक्षों तक पहुंचाना इसी व्यवस्था का हिस्सा है। कर्मचारियों की अनुपस्थिति में इन कामों का प्रभावित होना स्वाभाविक है।

भिवंडी में वरिष्ठ लिपिक जालंधर रामकृष्ण पाटील ने कहा कि अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारी भी उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की तरह ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं। न्यायिक व्यवस्था को संचालित करने में उनकी भूमिका को कम करके नहीं देखा जा सकता। वरिष्ठ लिपिक रेशमा अमोल निकते ने भी कर्मचारियों की मांग को उचित बताते हुए कहा कि समान काम करने के बावजूद वेतन में अंतर बने रहना न्यायसंगत नहीं है। महाराष्ट्र एवं गोवा बार काउंसिल के अध्यक्ष हर्षल पाटिल ने कर्मचारियों की भूमिका को बेहद अहम बताते हुए इस विवाद का समाधान सकारात्मक संवाद के माध्यम से निकालने पर जोर दिया। अधिवक्ता शैलेश गायकवाड ने भी सरकार से जल्द हस्तक्षेप कर ऐसा रास्ता निकालने की अपील की, जिससे कर्मचारियों की मांगों पर विचार हो और न्यायालयों का कामकाज लंबे समय तक बाधित न रहे। नवी मुंबई के बेलापुर न्यायालय में भी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण नियमित कामकाज लगभग पूरी तरह प्रभावित रहा। महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर लिपिक, चपरासी, वाहन चालक और गट 'क' के विभिन्न संवर्गों के कर्मचारी आंदोलन में शामिल हुए। कर्मचारियों का कहना है कि न्यायालयों में काम का दबाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके अनुरूप न तो कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है और न ही उन्हें उचित आर्थिक लाभ मिल रहे हैं। कर्मचारी गुरुनाथ माने के अनुसार, जिला और तालुका अदालतों में लाखों मामले लंबित हैं। ऐसे में कर्मचारियों पर काम का बोझ काफी अधिक है। कई कर्मचारियों को एक साथ चार-चार टेबलों का काम संभालना पड़ता है। एक ही कर्मचारी को अलग-अलग प्रकार की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, जिससे कार्यभार और मानसिक दबाव बढ़ता है। बेलापुर के कर्मचारियों ने वेतन में 20 से 30 हजार रुपये तक के अंतर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि समान जिम्मेदारियों के बावजूद आर्थिक स्तर पर भेदभाव जैसी स्थिति बनी हुई है। उनका कहना है कि आंदोलन केवल वेतन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समान काम के लिए समान वेतन और उचित आर्थिक अधिकारों की मांग है। कर्मचारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायालयों में समय पर काम पूरा कराने और न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद उनकी समस्याओं पर लंबे समय से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बेलापुर के अधिवक्ताओं ने भी कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया और सरकार से प्रस्ताव पर जल्द निर्णय लेने की अपील की।

किआ सोरेंटो ने पार किया 4,500 यूनिट्स होलसेल बिक्री का आंकड़ा

मुंबई। किआ इंडिया की प्रीमियम एसयूवी 'सोरेंटो' को बाजार में शानदार प्रतिक्रिया मिली है। सितंबर 2026 में बुकिंग शुरू होने के बाद कंपनी ने इसकी 4,500 होलसेल यूनिट्स का आंकड़ा पार कर लिया है। कंपनी के अनुसार, आधुनिक तकनीक, हाइब्रिड पावरट्रेन, प्रीमियम आराम और सुरक्षा फीचर्स इसकी लोकप्रियता के प्रमुख कारण हैं। किआ इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (सेल्स एंड मार्केटिंग) अतुल सूद ने इस उपलब्धि को ग्राहकों के भरोसे का प्रतीक बताया। सोरेंटो में



जनरेटिव एआई आधारित 'किआ एआई असिस्टेंट', 85 से अधिक कनेक्टेड कार फीचर्स, हाइब्रिड और डीजल इंजन विकल्प, AWD तथा 30 लेवल-2+ ADAS फीचर्स दिए गए हैं। यह 6 और 7 सीटों के विकल्प में उपलब्ध है।

अनंतपुर संयंत्र में निर्मित इस एसयूवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत डीजल मॉडल के लिए 27.99 लाख रुपये और हाइब्रिड मॉडल के लिए 29.49 लाख रुपये है। कंपनी तीन साल बाद 70 प्रतिशत तक सुनिश्चित रीसेल वैल्यू वाला बायबैक प्रोग्राम और प्रीमियम सर्विस सुविधाएं भी दे रही है।

'एक बरगद का पौधा लगाएं, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की विरासत बनाएं'

सुशीलादेवी सोशल वेल्फेअर फाउंडेशन की अनूठी पहल, महाराष्ट्र सहित देशभर में पौधारोपण और वृक्ष संवर्धन का आह्वान

पुणे। "बरगद का एक पौधा लगाओ, 500 साल पुण्य कमाओ" के संदेश के साथ पुणे की सुशीलादेवी सोशल वेल्फेअर फाउंडेशन ने पर्यावरण संरक्षण और वृक्ष संवर्धन के लिए देशव्यापी जनजागृति अभियान की पहल की है। संस्था के संस्थापक संतोष जाधव ने महाराष्ट्र सहित देश के सभी राज्यों के नागरिकों से अपने गांव, शहर, मोहल्ले और आसपास उपलब्ध सुरक्षित स्थानों पर बरगद के पौधे लगाने की अपील की है।

इस अभियान के तहत लोगों से घर में गमले या पौधारोपण बैग में बरगद का पौधा तैयार करने



और लगभग चार से पांच फीट बड़ा होने के बाद उसे उपयुक्त एवं सुरक्षित स्थान पर लगाने का आग्रह किया गया है। संस्था का सुझाव है कि मंदिर परिसर, गांव की सार्वजनिक जमीन, अनुपयोगी भूमि और वन क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन तथा संबंधित लोगों की सहमति से पौधारोपण किया जा सकता है। जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ और स्मृति दिवस जैसे अवसरों पर भी पौधा लगाकर उसे यादगार बनाया जा सकता है।

संस्था का लक्ष्य प्रत्येक गांव में कम से कम 50 से 500 बरगद के पौधे लगाने और उनके संरक्षण के लिए सामूहिक जिम्मेदारी विकसित करना है। फाउंडेशन के अनुसार, बरगद जैसे विशाल वृक्ष पक्षियों, मधुमक्खियों, तितलियों और गिलहरियों सहित अनेक जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। साथ ही वे मिट्टी के संरक्षण, जैव विविधता और स्थानीय पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

संस्था का मानना है कि बड़े पैमाने पर पौधारोपण के साथ उनका नियमित संरक्षण किया जाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित और समृद्ध पर्यावरण तैयार किया जा सकता है। पेड़ों से मिलने वाले प्राकृतिक लाभ, पत्तियों से बनने वाली जैविक खाद और जीव-जंतुओं के लिए सुरक्षित आवास पर्यावरण को मजबूत बनाने में सहायक होंगे।

संस्थापक संतोष जाधव ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल पौधे लगाने तक सीमित न रहें, बल्कि उनकी देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी निभाएं। उनका संदेश है कि एक बरगद का पौधा लगाना केवल आज का पर्यावरण बचाने का प्रयास नहीं, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रकृति की अनमोल विरासत तैयार करना है।

भुसावल में 14,562 मतदाताओं के खिलाफ फर्जी Form-7 आपत्तियों का आरोप, FIR दर्ज कर स्वतंत्र जांच की मांग

एक ही दिन में 186 व्यक्तियों के नाम पर दाखिल हुईं सभी आपत्तियां; प्रभावित मतदाताओं के नाम सूची से नहीं हटाने की मांग

मुंबई। जलगांव जिले के भुसावल विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान 14,562 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए कथित तौर पर फर्जी और नियमविरुद्ध Form-7 आपत्तियां दाखिल किए जाने का मामला सामने आया है। ये सभी आपत्तियां केवल 186 व्यक्तियों के नाम पर 12 अक्टूबर 2026 को एक ही दिन ऑफलाइन माध्यम से दाखिल की गईं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने इस मामले में FIR दर्ज कर जलगांव जिले के बाहर के किसी वरिष्ठ अधिकारी से स्वतंत्र एवं समयबद्ध जांच कराने की मांग की है। उन्होंने प्रभावित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से नहीं हटाने और जिम्मेदार व्यक्तियों व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। सपकाल ने अपने पत्र में कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने 9 अक्टूबर 2026 को पत्र क्रमांक 23/Inst/2026-ERS के माध्यम से निर्देश जारी किए थे कि कोई भी व्यक्तिगत मतदाता दावे और आपत्तियां दाखिल करने की पूरी अवधि में अधिकतम 10 Form-7 आवेदन ही जमा कर सकता है। यह सीमा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों पर लागू है। इन निर्देशों के महज तीन दिन बाद भुसावल में एक ही दिन में



186 व्यक्तियों के नाम पर हजारों आपत्तियां दाखिल होना गंभीर सवाल खड़े करता है।

पत्र के अनुसार, जिन व्यक्तियों के नाम पर ये आवेदन दाखिल किए गए हैं, उनमें से कुछ लोगों ने लिखित रूप से स्पष्ट किया है कि उन्होंने ये आवेदन नहीं किए हैं। तीन व्यक्तियों के नाम पर कुल 463 आपत्तियां दाखिल होने की जानकारी दी गई है। इनमें से दो व्यक्तियों के लिखित निवेदनों और कार्यालयीन प्राप्ति की प्रतियां पत्र के साथ परिशिष्ट-ब के रूप में संलग्न की गई हैं। इसके अलावा कई अन्य लोगों ने भी स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारियों को मौखिक रूप से बताया है कि उन्हें Form-7 आवेदनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

सपकाल ने आरोप लगाया है कि उपलब्ध दस्तावेजों से यह मामला तीसरे पक्ष के लोगों द्वारा सुनियोजित तरीके से आवेदन तैयार किए जाने की आशंका पैदा करता है। एक ही व्यक्ति के नाम पर मतदाता सूची के 12 से 20 अलग-अलग भागों के मतदाताओं के खिलाफ आपत्तियां दर्ज की गई हैं। कई मामलों में आवेदक ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी हैं, जबकि आपत्तियां दूसरे क्षेत्रों के मतदाताओं के खिलाफ दाखिल की गई हैं। कुछ आवेदकों के नाम पर अलग-अलग भागों में 20 या 25 आपत्तियों के समान समूह भी दिखाई देते हैं।

पत्र में यह भी कहा गया है कि आवेदनों की प्रतियों में एक ही व्यक्ति का नाम अलग-अलग तरीके से लिखा गया है। कुछ फॉर्म पर तीन से चार अलग-अलग हस्ताक्षर और अलग-अलग स्याही का इस्तेमाल दिखाई देता है। कई आपत्तियों में मतदाताओं को अनुपस्थित बताया गया है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि संबंधित मतदाता अपने पंजीकृत पते पर ही रह रहे हैं। SIR प्रक्रिया के दौरान घर-घर सत्यापन के बाद ही उनके नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किए गए थे।

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने अपने पत्र में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धाराओं 13A, 13CC और 32 का उल्लेख करते हुए कहा है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की निगरानी और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के लाल बाबू हुसैन बनाम मतदाता पंजीकरण अधिकारी (1995) 3 SCC 100 मामले का हवाला देते हुए कहा कि मतदाता सूची में पहले से दर्ज किसी व्यक्ति का नाम हटाने से पहले उसे नोटिस देना, पक्ष रखने का उचित अवसर देना और ठोस आधार होना आवश्यक है।

सपकाल ने मांग की है कि पूरे मामले की जांच जलगांव जिले के बाहर के किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराई जाए। जांच में यह पता लगाया जाए कि आवेदन किसने जमा किए, उन्हें किस अधिकारी या कर्मचारी ने स्वीकार किया, आवक रजिस्टर में उनकी प्रविष्टियां और प्राप्ति रसीदें उपलब्ध हैं या नहीं तथा निर्वाचन आयोग की निर्धारित सीमा के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में आवेदन किस आधार पर स्वीकार किए गए।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता और प्रत्येक पात्र नागरिक का मताधिकार लोकतंत्र की बुनियाद है। कथित फर्जी आपत्तियों के आधार पर किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाना चाहिए। कांग्रेस ने प्रभावित मतदाताओं को तत्काल राहत देने, FIR दर्ज कराने, निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों एवं अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

महाराष्ट्र में लिफ्ट सुरक्षा के नए नियम लागू, बच्चों की आवाजाही पर भी सख्ती

मुंबई। महाराष्ट्र में लिफ्ट और एस्केलेटर से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने तथा आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने नए सुरक्षा नियम लागू कर दिए हैं। ये प्रावधान 1 नवंबर 2026 से प्रभावी हो चुके हैं। नए नियमों के तहत अब 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी वयस्क की देखरेख के बिना लिफ्ट या एस्केलेटर का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही लिफ्टों के नियमित रखरखाव, तकनीकी जांच, बीमा और आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था को भी अनिवार्य बनाया गया है। इन नियमों का सीधा असर मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र की हाउसिंग सोसाइटियों, अपार्टमेंट परिसरों, व्यावसायिक इमारतों और लिफ्ट संचालकों पर पड़ेगा।

राज्य सरकार का यह कदम लिफ्ट से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट रोजमर्रा की जरूरत बन चुकी है। आवासीय सोसाइटियों से लेकर अस्पतालों, मॉल, कार्यालयों और सार्वजनिक भवनों तक बड़ी संख्या में लोग प्रतिदिन इनका उपयोग करते हैं। बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए तो लिफ्ट कई बार आवाजाही का सबसे सुविधाजनक साधन होती है। ऐसे में लिफ्ट की तकनीकी खराबी, अचानक बंद हो जाना, दरवाजों में फंसना या सुरक्षा उपकरणों का ठीक से काम नहीं करना गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। नए नियमों के माध्यम से सरकार ने उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के साथ-साथ लिफ्ट के रखरखाव की जिम्मेदारी भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। नए प्रावधानों में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव बच्चों के लिफ्ट और एस्केलेटर इस्तेमाल को लेकर किया गया है। अब 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अकेले इनका उपयोग नहीं कर सकेंगे। उन्हें किसी वयस्क के साथ ही लिफ्ट या एस्केलेटर में जाने की अनुमति होगी। इसका उद्देश्य बच्चों को संभावित दुर्घटनाओं से बचाना है। कम उम्र के बच्चे अक्सर लिफ्ट के बटन से खेलते हैं, दरवाजे खुलने-बंद होने के दौरान लापरवाही कर सकते हैं या एस्केलेटर पर संतुलन बिगड़ने के कारण दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। कई बार बच्चों को लिफ्ट के तकनीकी संचालन और आपात स्थिति में अपनाए जाने वाले उपायों की जानकारी भी नहीं होती। ऐसे में किसी बड़े व्यक्ति की मौजूदगी उनकी सुरक्षा के लिहाज से जरूरी मानी गई है। अभिभावकों और सोसाइटियों को भी अब इस नियम के प्रति जागरूक रहना होगा। नए नियमों के तहत हाउसिंग सोसाइटियों की जिम्मेदारी पहले से अधिक बढ़ा दी गई है। अब प्रत्येक सोसाइटी को अधिकृत ठेकेदार या सेवा प्रदाता के माध्यम से हर महीने लिफ्ट की सर्विसिंग करानी होगी। इसका उद्देश्य छोटी तकनीकी खराबियों की समय रहते पहचान करना और उन्हें बड़ी दुर्घटना में बदलने से रोकना है। नियमित सर्विसिंग के दौरान लिफ्ट की मोटर, ब्रेकिंग सिस्टम, दरवाजों की कार्यप्रणाली, सेंसर, केबल, बिजली आपूर्ति और आपातकालीन व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण हिस्सों की जांच की जा सकेगी। यदि किसी उपकरण में खराबी पाई जाती है तो उसे समय रहते ठीक कराया जा सकेगा। इससे लिफ्ट अचानक बंद होने या यात्रियों के बीच में फंस जाने जैसी घटनाओं की आशंका कम करने में मदद मिलेगी।

मासिक सर्विसिंग के अलावा प्रत्येक लिफ्ट का साल में एक बार सुरक्षा ऑडिट कराना भी अनिवार्य किया गया है। इस व्यवस्था के तहत लिफ्ट की संपूर्ण तकनीकी स्थिति और सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी। केवल सामान्य मरम्मत या नियमित सफाई को पर्याप्त नहीं माना जाएगा, बल्कि यह सुनिश्चित करना होगा कि लिफ्ट के सभी जरूरी सुरक्षा उपकरण सही ढंग से काम कर रहे हैं। सुरक्षा ऑडिट से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि लिफ्ट कितनी सुरक्षित है और उसमें किन तकनीकी सुधारों की आवश्यकता है। इससे पुरानी लिफ्टों की स्थिति का भी नियमित आकलन हो सकेगा। सोसाइटियों को इस प्रक्रिया को केवल औपचारिकता के रूप में नहीं, बल्कि निवासियों की सुरक्षा से जुड़ी अनिवार्य जिम्मेदारी के रूप में लेना होगा।

सरकार ने लिफ्टों के लिए थर्ड पार्टी बीमा भी अनिवार्य कर दिया है। इस प्रावधान का उद्देश्य लिफ्ट दुर्घटना की स्थिति में प्रभावित लोगों के हितों की सुरक्षा करना और संबंधित पक्षों की जवाबदेही तय करना है। बहुमंजिला इमारतों में बड़ी संख्या में लोग लिफ्ट का उपयोग करते हैं। यदि तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारण से दुर्घटना होती है तो यात्रियों को शारीरिक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। थर्ड पार्टी बीमा की अनिवार्यता से ऐसी स्थिति में प्रभावित पक्षों को बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था मजबूत हो सकेगी। इससे लिफ्ट के रखरखाव और संचालन से जुड़े पक्षों को भी सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेने का संदेश मिलेगा। पुरानी लिफ्टों को आधुनिक सुरक्षा मानकों के अनुरूप बनाने के लिए भी सरकार ने समयसीमा निर्धारित की है। इनके लिए सीसीटीवी कैमरे, स्वचालित बचाव उपकरण यानी ऑटोमैटिक रेस्क्यू डिवाइस और ओवरलोड सुरक्षा उपकरण लगाना अनिवार्य होगा।

संपादकीय

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित करना जरूरी

ऐसे वक्त में जब दुनिया में तकनीकी वर्चस्व वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के केंद्र में आ गया है, 'सैन 'फ्रांसिस्को घोषणा' के गहरे निहितार्थ और महत्व को समझना कठिन नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घोषणा पर अमेरिका और भारत सहित नौ अन्य विकसित देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता इस बात पर जोर देता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बल पर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर घोषणा का एक अघोषित उद्देश्य इस उभरती हुई नई प्रौद्योगिकी में चीन के निरंतर बढ़ते दबदबे का मुकाबला करना भी है। चीन ने एक सुनियोजित ढंग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में व्यापक और दीर्घकालीन निवेश किया है। इसमें दो राय नहीं कि उसकी उपलब्धियां अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने वाली हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने 'सैन फ्रांसिस्को घोषणा' को हकीकत बनाने को प्राथमिकता दी है। अमेरिका दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती भूमिका के चलते इस दौर को 'सुपर इंटेलिजेंस युग' का नाम देता है। अमेरिका की 'पैक्स सिलिका' पहल एक बुनियादी सच्चाई को स्वीकार करती है कि दुनिया का कोई भी देश अकेले बूते पर बेहद जटिल प्रक्रिया वाले एआई इकोसिस्टम की हर कड़ी को सुरक्षित नहीं कर सकता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो महत्वपूर्ण खनिजों और सेमीकंडक्टर निर्माण से लेकर ऊर्जा नेटवर्क और डिजिटल बुनियादी ढांचे तक, तकनीकी प्रगति आपस में जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर करती है। इस श्रृंखला में किसी भी तरह का अवरोध किसी भी देश के आर्थिक ढांचे को गहरे तक प्रभावित कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इन नेटवर्कों में यदि किसी भी तरह का व्यवधान पैदा होता है तो उसके दूरगामी आर्थिक और भू-राजनीतिक दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। जो किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिये, इस सुपर इंटेलिजेंस युग वाले दौर में तमाम चुनौतियां खड़ी कर सकता है।

निश्चित रूप से 'सैन फ्रांसिस्को घोषणा' पर भारत का हस्ताक्षर करना एआई के दौर में हमारी उपलब्धियों की वैश्विक स्वीकार्यता का ही परिचायक है। भारत के लिए अमेरिका और अन्य विकसित देशों के साथ शामिल होना जहां एक ओर अच्छा रणनीतिक अवसर है, वहीं देश को जिम्मेदारियों का अहसास भी कराता है। भारत हालिया वर्षों में एक उभरते हुए टेक्नोलॉजी बाजार के रूप में सामने आया है। भारत की महत्वाकांक्षा वैश्विक सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की रही है। हाल के वर्षों में भारत ने आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और कई मध्यपूर्व के देशों के साथ मजबूत व्यापारिक साझेदारियां की हैं। जाहिर तौर पर ये विकसित व मजबूत आर्थिक देश जब कोई साझेदारी करते हैं तो उन्हें कुछ पाने की ही उम्मीद होती है। ऐसे में भारत इन मजबूत साझेदारियों, विभिन्न आपूर्ति श्रृंखलाओं, निवेश और उन्नत तकनीकों का बेहतर ढंग से लाभ उठा सकता है। इस बात में दो राय नहीं हो सकती है कि इन भरोसेमंद साझेदारों के साथ सहयोग करने से भारत पहले की तरह चंद देशों पर अत्यधिक निर्भरता कम कर सकता है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में एक देश पर निर्भर रहना आर्थिक संप्रभुता के लिये चुनौती बन सकती है। ऐसे में नये भरोसेमंद साझेदारों के साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में मदद मिल सकती है। विडंबना यह भी है कि यह घोषणा ऐसे समय में सामने आई है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति की अगुवाई करने वाली शीर्ष कंपनियों में से एक-एनवीडिया विवादों में घिरी है और उसके शेयरों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। विवाहेतर संबंधों व कथित चीनी जासूस से संबंधों को लेकर इसके संस्थापक जेनसेन हुआंग को एनवीडिया से बाहर जाना पड़ा है। इस अनिश्चितता के बीच, टेक कंपनियों द्वारा एनवीडिया की चिप्स और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में किए जा रहे भारी निवेश की निरंतरता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। निस्संदेह, अमेरिका के नेतृत्व वाली इस पहल की सफलता टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, निवेश और मजबूत घरेलू क्षमताओं पर निर्भर करेगी। अंततः एआई आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने का मतलब सिर्फ तकनीक पर नियंत्रण रखना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है एआई के फायदे भरोसेमंद हों, सभी की पहुंच में हों और इसे व्यापक रूप से साझा किया जा सके।

सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली ! दुनिया में अशांति फैलाने वाले Trump-Putin-Xi करेंगे शांति की बात

> हर साल नोबेल शांति पुरस्कार पाने की ख्वाहिश जाहिर करने वाले डोनाल्ड ट्रंप की शांति वाली मंशा पर सवाल उठना लाजिमी है। दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पहले संबोधन में दुनिया को युद्धों से मुक्त कराने और शांति स्थापित करने का वादा करने वाले ट्रंप की नीतियां इसके ठीक उलट दिशा में जाती दिखाई दी हैं।



दुनिया में वैसे तो तमाम तरह के विरोधाभास देखने को मिलते रहे हैं, लेकिन अब दुनिया की तीन सबसे बड़ी शक्तियां खुद एक ऐसा कदम उठाने जा रही हैं, जिसे इस दौर का सबसे बड़ा विरोधाभास कहा जा सकता है। दुनिया को युद्ध, तनाव और टकराव की आग में झोंकने वाली ये तीनों ताकतें अब एक मंच पर बैठकर शांति और वैश्विक स्थिरता पर चर्चा करने जा रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इस प्रस्तावित मुलाकात को लेकर पूरी दुनिया में उत्सुकता है। उत्सुकता इसलिए है क्योंकि ट्रंप लगातार ईरान को सैन्य कार्रवाई की धमकियां दे रहे हैं, पुतिन लगभग पांच साल से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे हैं और जिनपिंग ताइवान से लेकर दक्षिण चीन सागर तक अपनी सैन्य और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं से पड़ोसी देशों की चिंता बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब यही तीनों नेता दुनिया को शांति का रास्ता दिखाने के लिए एक साथ बैठेंगे। ऐसे में सवाल सिर्फ इस बैठक के एजेंडे का नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपे उन सामरिक और रणनीतिक उद्देश्यों का भी है, जिनका असर आने वाले समय में पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ सकता है।देखा जाये तो हर साल नोबेल शांति पुरस्कार पाने की ख्वाहिश जाहिर करने वाले डोनाल्ड ट्रंप की शांति वाली मंशा पर सवाल उठना लाजिमी है। दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पहले संबोधन में दुनिया को युद्धों से मुक्त कराने और शांति स्थापित करने का वादा करने वाले ट्रंप की नीतियां इसके ठीक उलट दिशा में जाती दिखाई दी हैं। ईरान के साथ सैन्य टकराव, अमेरिकी हमले और तेहरान के जवाबी पलटवार ने पूरे मध्य पूर्व को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया। इस संघर्ष ने न केवल बड़ी संख्या में लोगों की जान ली, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब पर भी महंगाई का बोझ बढ़ाया। ईरान को लेकर ट्रंप का लगातार बदलता रुख कभी सैन्य धमकियों, कभी अधिकतम दबाव और कभी बातचीत की पेशकश के रूप में सामने आता रहा है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि शेनझेन में होने वाली बैठक ट्रंप की वास्तविक शांति पहल है या फिर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के मुखिया के रूप में अपना दबदबा स्थापित करने का एक और मंच है? दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन हैं। यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध लगभग पांच साल पूरे करने की तरफ बढ़ रहा है। अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है, कई शहर तबाह हुए हैं और यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था दशकों के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। जिस युद्ध को रूस ने अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों का सवाल बताकर शुरू किया था, वह अब वैश्विक शक्ति संतुलन की सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल हो चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि पुतिन शांति की बातचीत में क्या प्रस्ताव लेकर पहुंचेंगे? क्या वह युद्ध समाप्त करने का रास्ता तलाशेंगे या अपनी सैन्य कार्रवाई से हासिल किए गए क्षेत्रीय और राजनीतिक लाभ को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाने की कोशिश करेंगे? पुतिन के लिए इस बैठक का एक बड़ा फायदा यह भी है कि अमेरिकी और चीनी राष्ट्रपति के साथ एक ही मंच पर बैठना रूस की अंतरराष्ट्रीय स्थिति को नई वैधता और प्रतिष्ठा दे सकता है। देखा जाये तो यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों की ओर से रूस को अलग-थलग करने की कोशिशों के बीच यह तस्वीर मॉस्को के लिए अपने आप में बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि होगी।

कथित शांति की चाह रखने वाले तीसरे खिलाड़ी शी जिनपिंग हैं। देखा जाये तो चीन एक तरफ खुद को वैश्विक शांति और सहयोग का समर्थक बताता है, दूसरी तरफ ताइवान को लेकर उसकी सैन्य और राजनीतिक धमकियां लगातार क्षेत्रीय तनाव बढ़ाती हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन की विस्तारवादी गतिविधियां फिलीपींस, वियतनाम और अन्य पड़ोसी देशों की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाती रही हैं। समुद्री क्षेत्रों पर दावेदारी, सैन्य ठिकानों का विस्तार और क्षेत्र में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिशें चीन की महत्वाकांक्षाओं को उजागर करती हैं। सवाल है कि ताइवान और दक्षिण चीन सागर में दबाव की राजनीति करने वाले जिनपिंग शेनझेन में किस तरह की शांति व्यवस्था की बात करेंगे? क्या चीन अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं पर कोई समझौता करने के लिए तैयार है? देखा जाये तो इस बैठक के मायने केवल शांति की अपील तक सीमित नहीं हैं। इसके पीछे परमाणु हथियारों का संतुलन, वैश्विक सैन्य वर्चस्व, आर्थिक हित और नई विश्व व्यवस्था की लड़ाई भी छिपी है। अमेरिका चाहता है कि चीन भी परमाणु हथियारों पर नियंत्रण से जुड़ी बातचीत में शामिल हो। रूस के साथ अमेरिका की पुरानी परमाणु हथियार नियंत्रण व्यवस्था समाप्त हो चुकी है और वाशिंगटन अब बीजिंग को भी इस व्यवस्था का हिस्सा बनाना चाहता है। लेकिन चीन के परमाणु हथियारों का भंडार अमेरिका और रूस की तुलना में काफी छोटा है। ऐसे में जिनपिंग क्यों ऐसी बातचीत में शामिल होंगे जिसमें उनकी सामरिक बढ़त के बजाय उनकी शक्ति को सीमित करने पर चर्चा हो? देखा जाये तो पुतिन के लिए यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका के साथ सीधे संवाद का रास्ता महत्वपूर्ण है, जबकि जिनपिंग के लिए यह साबित करने का अवसर है कि दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच किसी भी नए वैश्विक समीकरण में चीन की भूमिका निर्णायक होगी। वहीं ट्रंप के लिए यह मुलाकात अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी नेतृत्व क्षमता और कूटनीतिक प्रभाव दिखाने का मौका है। साथ ही इस बैठक को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया की व्यवस्था अब तीन महाशक्तियों के आपसी समझौतों से तय होगी? क्या छोटे देशों की संप्रभुता, उनकी सुरक्षा और उनके भविष्य पर भी इन तीनों की बातचीत का प्रभाव पड़ेगा? यूक्रेन, ताइवान और दक्षिण चीन सागर से जुड़े देशों की चिंता इसी वजह से बढ़ रही है। कहीं यह मुलाकात 1945 के याल्टा सम्मेलन जैसी किसी नई वैश्विक शक्ति व्यवस्था की शुरुआत तो नहीं बनने जा रही, जहां बड़ी ताकतें अपने हितों के अनुसार दुनिया के प्रभाव क्षेत्रों का निर्धारण करने लगें? बहरहाल, तीन नेता, तीन महाशक्तियां और पूरी दुनिया के भविष्य से जुड़े कई बड़े सवाल सामने हैं। शांति की मेज पर आमने-सामने बैठने जा रहे इन तीनों नेताओं की असली परीक्षा इस बात से होगी कि वे अपनी सामरिक महत्वाकांक्षाओं और वैश्विक वर्चस्व की होड़ से कितना पीछे हटने को तैयार हैं। क्या ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग दुनिया को शांति का नया रास्ता दिखा पाएंगे या उनकी यह मुलाकात भी महज कूटनीतिक शक्ति प्रदर्शन बनकर रह जाएगी? अंत में एक बार फिर से वही सवाल उठता है कि जो नेता अपने-अपने मोर्चों पर तनाव और टकराव की राजनीति कर रहे हैं, क्या वे वास्तव में दुनिया को अशांति से बाहर निकालने का इरादा रखते हैं?

सरोकार

अभावों से आसमान तक, हौसले ने लिखी कामयाबी की नई कहानी

किसी इंसान की पहचान इस बात से नहीं होती कि उसे जिंदगी में कितनी सुविधाएं मिलीं, बल्कि इस बात से होती है कि उसने मुश्किल हालात में कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। दुनिया में ऐसे अनेक लोग हुए हैं, जिन्होंने अभावों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हीं परिस्थितियों को अपनी ताकत में बदलकर इतिहास रच दिया। ब्रिटेन के मशहूर फॉर्मूला वन रेसर लुईस हैमिल्टन भी ऐसी ही शख्सियत हैं। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण, पारिवारिक त्याग और अटूट आत्मविश्वास का ऐसा उदाहरण है, जो बताता है कि सपने देखने के लिए दौलत की नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए मजबूत इरादों की जरूरत होती है। 7 जनवरी 1985 को इंग्लैंड के स्टीवनेज में जन्मे लुईस हैमिल्टन का बचपन किसी संपन्न परिवार के बच्चे जैसा नहीं था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी, लेकिन उनके सपने असाधारण थे। बचपन से ही उन्हें तेज रफ्तार गाड़ियों और रेसिंग का आकर्षण था। महज आठ वर्ष की उम्र में उन्होंने कार्टिंग से अपने खेल जीवन की शुरुआत की। छोटी सी रेसिंग गाड़ी पर बैठकर ट्रैक पर उतरने वाले इस बच्चे को शायद उस समय खुद भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन पूरी दुनिया उसकी रफ्तार और हुनर की मिसाल देगी।

रेसिंग का शौक पालना और उसे पेशेवर करियर में बदलना दो अलग-अलग बातें हैं। इस खेल में वाहन, उपकरण, प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं का खर्च काफी अधिक होता है। लुईस के परिवार के लिए इन सभी जरूरतों को पूरा करना आसान नहीं था। उनके पिता एंथनी हैमिल्टन ने बेटे की प्रतिभा को पहचाना और उसे आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी सीमित आमदनी के बावजूद बेटे के सपनों को टूटने नहीं दिया। इसके लिए उन्हें एक साथ कई काम करने पड़े। वे आईटी मैनेजर की नौकरी करते थे, अतिरिक्त समय में निर्माण स्थलों पर मेहनत करते थे और रात में बर्तन धोने जैसे काम भी करते थे। उनका पूरा प्रयास यही रहता था कि बेटे को अभ्यास और प्रतियोगिताओं के लिए जरूरी सुविधाएं मिलती रहें।

परिवार की आर्थिक तंगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई बार रेसिंग के लिए नए टायर खरीदना भी संभव नहीं होता था। ऐसे में एंथनी दूसरी टीमों के इस्तेमाल किए हुए टायर जुटाकर बेटे की गाड़ी तैयार करते थे। जहां अन्य खिलाड़ियों के पास महंगे उपकरण और आधुनिक सुविधाएं थीं, वहीं लुईस को सीमित संसाधनों के साथ अपनी प्रतिभा साबित करनी पड़ती थी। लेकिन उनके पिता ने कभी परिस्थितियों को बेटे की राह का अंतिम पड़ाव नहीं बनने दिया।

लुईस का संघर्ष केवल पैसों की कमी तक सीमित नहीं था। रेसिंग की दुनिया में उस समय अश्वेत खिलाड़ियों की संख्या बेहद कम थी। कार्टिंग ट्रैक पर वे अक्सर अकेले अश्वेत बच्चे होते थे। उन्हें नस्लीय भेदभाव, अपमानजनक टिप्पणियों और उपेक्षा का सामना करना पड़ता था। कई बार उनकी त्वचा के रंग को लेकर उनका मजाक उड़ाया जाता था। ऐसे माहौल में किसी छोटे बच्चे के लिए खुद को संभालना आसान नहीं होता, लेकिन लुईस ने हार मानने के बजाय अपनी प्रतिभा को ही सबसे बड़ा जवाब बनाया। हर प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने की उनकी जिद धीरे-धीरे उनकी पहचान बनती चली गई। पिता की मेहनत और बेटे के जुनून का असर जल्द ही दिखाई देने लगा। वर्ष 1998 में लुईस को मैकलारेन के ड्राइवर डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल किया गया। यह उनके करियर की बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद उन्होंने विभिन्न जूनियर रेसिंग प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वर्ष 2005 में उन्होंने फॉर्मूला श्री यूरो सीरीज का खिताब जीता और 2006 में जीपी2 चैंपियन बने। लगातार शानदार प्रदर्शन ने उनके लिए फॉर्मूला वन के दरवाजे खोल दिए।

वर्ष 2007 में मैकलारेन टीम की ओर से उन्होंने फॉर्मूला वन में पदार्पण किया। अपने पहले ही सीजन में उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उसने अनुभवी खिलाड़ियों और रेसिंग विशेषज्ञों को हैरान कर दिया। वे खिताब जीतने के बेहद करीब पहुंचे और अगले वर्ष अपनी पिछली कमी को पूरा कर दिया। वर्ष 2008 में उन्होंने ब्राजील ग्रां प्री के रोमांचक मुकाबले में विश्व चैंपियनशिप अपने नाम की। महज 23 वर्ष की उम्र में वे फॉर्मूला वन के इतिहास के पहले अश्वेत विश्व चैंपियन बन गए। यह उपलब्धि उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ-साथ खेल जगत के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गई। पहली विश्व चैंपियनशिप जीतने के बाद भी उनका सफर नहीं रुका। वर्ष 2013 में वे मर्सिडीज टीम से जुड़े और इसके बाद उनकी सफलता का नया दौर शुरू हुआ। उन्होंने 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 और 2020 में विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता। इस तरह उनके नाम कुल सात विश्व खिताब दर्ज हो गए। उन्होंने महान रेसर माइकल शूमाकर के सात विश्व चैंपियनशिप खिताबों के रिकॉर्ड की बराबरी की। रेस जीत, पोल पोजीशन और पोडियम फिनिश के मामले में भी उन्होंने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कीं। लुईस की खासियत केवल उनकी तेज रफ्तार नहीं है, बल्कि दबाव में धैर्य बनाए रखने और आखिरी क्षण तक मुकाबला करने की क्षमता भी है। उन्होंने कई बार ऐसी परिस्थितियों में जीत हासिल की, जब उनके सामने चुनौतियां बेहद कठिन थीं। वे जानते थे कि एक छोटी सी गलती भी वर्षों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। इसलिए अभ्यास, अनुशासन और निरंतर सुधार को उन्होंने अपनी सफलता का आधार बनाया। रेसिंग के अलावा लुईस हैमिल्टन सामाजिक समानता और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ भी मुखर रहे हैं। वे खेलों में सभी वर्गों की भागीदारी और युवाओं को समान अवसर देने की वकालत करते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि आने वाली पीढ़ियों को उन कठिनाइयों से न गुजरना पड़े, जिनका सामना उन्हें अपने शुरुआती दिनों में करना पड़ा था।

सपा-कांग्रेस गठबंधन: सीटों के पेच में उलझती सियासी राह

उत्तर प्रदेश की सियासी धरती हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति की दिशा और दशा तय करती रही है। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की आहट तेज होने के साथ ही विपक्षी खेमे, विशेषकर 'इंडिया' गठबंधन के दो प्रमुख स्तंभों—समाजवादी पार्टी और कांग्रेस—के बीच सीटों के तालमेल को लेकर हलचल अपने चरम पर है। नई दिल्ली में 17 नवंबर 2026 को दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच सीट बंटवारे पर होने वाली बहुप्रतीक्षित औपचारिक बैठक का ऐन वक्त पर टल जाना, सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलों और चर्चाओं को जन्म दे रहा है। हालांकि, इस स्थगन को केवल टकराव के रूप में देखने के बजाय गठबंधन की आंतरिक जटिलताओं, महत्वाकांक्षाओं के टकराव और चुनावी यथार्थ के बीच संतुलन साधने की एक कठिन कवायद के रूप में समझा जाना चाहिए। बैठक टलने के पीछे भले ही समन्वय समितियों के गठन और प्रारंभिक तैयारी का हवाला दिया गया हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि दोनों दलों के बीच सीटों की संख्या और दावेदारी को लेकर अभी तक कोई सर्वमान्य फॉर्मूला नहीं बन पाया है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में कांग्रेस की वह प्रारंभिक सूची है, जिसमें उसने उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से लगभग 181 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। कांग्रेस के इस प्रस्ताव ने समाजवादी पार्टी के खेमे में स्वाभाविक रूप से असहजता पैदा कर दी है। सपा नेतृत्व, जो राज्य में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते खुद को गठबंधन के 'बड़े भाई' की भूमिका में देखता है, इतनी बड़ी संख्या में सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों और विभिन्न समाचार माध्यमों की खबरों के अनुसार, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 50 से 80 सीटों के दायरे में ही सीमित रखना चाहती है। सीटों की मांग और पेशकश के बीच का यह विशाल अंतर ही वह मुख्य पेच है, जिसके चलते 17 नवंबर की औपचारिक बैठक को तीन-चार दिनों के लिए आगे बढ़ाना पड़ा। सोनिया गांधी की पुस्तक के विमोचन के अवसर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हुई अनौपचारिक बातचीत में यह सहमति बनी कि शीर्ष स्तर पर अंतिम मुहर लगने से पहले दोनों दल अपनी-अपनी समन्वय समितियों के माध्यम से जमीनी हकीकत और दावेदारी का आकलन करें। कांग्रेस ने इसके लिए प्रियंका गांधी वाड्रा, के.सी. वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा और इमरान मसूद जैसे वरिष्ठ नेताओं की पांच सदस्यीय समिति का गठन कर अपनी गंभीरता दर्शाई है।गठबंधन की इस खींचतान को समझने के लिए दोनों दलों के तर्कों और उनके पीछे के चुनावी आंकड़ों पर नजर डालना आवश्यक है। कांग्रेस का उत्साह मुख्य रूप से 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणामों से उपजा है, जहां सपा और कांग्रेस ने मिलकर उत्तर प्रदेश की 80 में से 43 संसदीय सीटों पर जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में सपा को 37 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली थीं, जिससे विपक्षी गठबंधन को एक नई संजीवनी प्राप्त हुई थी। कांग्रेस का मानना है कि लोकसभा चुनावों के बाद राज्य में उसका जनाधार बढ़ा है और संगठन में नई जान फूंकी गई है। इसी आधार पर कांग्रेस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 67, अवध क्षेत्र की 51 और बुंदेलखंड की 9 सीटों सहित कुल 181 सीटों की सूची तैयार की है। कांग्रेस के रणनीतिकारों का यह भी तर्क है कि यदि 2024 के लोकसभा परिणामों के अनुपात को आधार बनाया जाए, तो भी उसे सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसके विपरीत, समाजवादी पार्टी के पास 2022 के विधानसभा चुनावों के ठोस आंकड़े हैं, जो कांग्रेस के दावों पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने दम पर लड़ते हुए महज दो सीटों पर जीत हासिल की थी, उसका वोट प्रतिशत चार फीसदी से भी नीचे (3.84 प्रतिशत) सिमट गया था और उसके अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। इसके अलावा, हाल के वर्षों में हुए विधानसभा उपचुनावों के नतीजों ने भी सपा को यह अहसास कराया है कि जमीनी स्तर पर संगठन की मजबूती और कैडर वोट का हस्तांतरण ही जीत की असली गारंटी है। अखिलेश यादव ने दिल्ली पहुंचने पर मीडिया से बातचीत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यावहारिक कसौटी का उल्लेख किया है—'जिताऊ क्षमता')। उनका स्पष्ट कहना है कि गठबंधन का मुख्य उद्देश्य अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को हराना है, और इसलिए जिस सीट पर जिस दल का उम्मीदवार जीतने की सबसे मजबूत स्थिति में होगा, वही वहां से चुनाव लड़ेगा। राजनीति के व्यावहारिक धरातल पर सपा प्रमुख का यह तर्क अत्यंत वजनदार प्रतीत होता है।

नजरिया

तुलसी माता की आराधना से संवरेंगे भाग्य, चालीसा पाठ से घर में आएगी सुख-शांति और समृद्धि



उत्तराम्नाय ज्योतिष्पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती

हिंदू धर्म में कुछ पौधे ऐसे हैं, जिन्हें प्रकृति की अनमोल देन होने के साथ-साथ देवी-देवताओं का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। तुलसी उन्हीं में से एक है। सनातन परंपरा में तुलसी को पवित्रता, समर्पण, भक्ति और शुभता का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है और जहां प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक उसकी पूजा की जाती है, वहां सकारात्मकता और मंगलकारी वातावरण बना रहता है। भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी की आराधना का विशेष धार्मिक महत्व है। यही वजह है कि विष्णु पूजा में तुलसी दल अर्पित किए बिना भोग अधूरा माना जाता है। धार्मिक विश्वास है कि नियमित रूप से तुलसी चालीसा का पाठ करने से भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इससे जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना करने का साहस मिलता है और परिवार में सुख, शांति तथा समृद्धि बनी रहती है।

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी का संबंध देवी वृंदा से जुड़ा हुआ है। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थीं और उनकी भक्ति तथा तपस्या का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु ने उन्हें तुलसी के रूप में सदैव पूजनीय रहने का वरदान दिया था। इसी कारण तुलसी को हरिप्रिया कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु, श्रीकृष्ण और शालिग्राम की पूजा में तुलसी दल अर्पित करने से पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है। यही कारण है कि घरों और मंदिरों में तुलसी का पौधा लगाकर उसकी नियमित पूजा करने की परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। तुलसी चालीसा में माता तुलसी की महिमा, उनकी कृपा और धार्मिक महत्व का गुणगान किया गया है। इसमें तुलसी माता के स्वरूप और भक्तों के कल्याण से जुड़ी मान्यताओं का वर्णन मिलता है। श्रद्धालु प्रतिदिन इसका पाठ करके अपने परिवार की खुशहाली और जीवन में आने वाली बाधाओं से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि नियमित पाठ से व्यक्ति के मन में भक्ति भाव मजबूत होता है और वह अपने दैनिक जीवन में सकारात्मक विचारों को स्थान देने लगता है। पूजा-पाठ के दौरान मन को एकाग्र करना, ईश्वर का स्मरण करना और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगना आध्यात्मिक जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम माना जाता है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी चालीसा का पाठ करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चूंकि तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए उनकी आराधना को घर में धन-धान्य और सौभाग्य बढ़ाने वाला बताया गया है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि नियमित पाठ से आर्थिक परेशानियों में कमी आती है और परिवार में खुशहाली का वातावरण बनता है। जीवन में धन का महत्व केवल संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति, संतोष और सुरक्षित भविष्य भी समृद्धि का हिस्सा हैं। तुलसी माता की पूजा व्यक्ति को संतोष, परिश्रम और उचित आचरण के साथ जीवन बिताने की प्रेरणा देती है।

ज्योतिषीय मान्यताओं में भी तुलसी का विशेष स्थान बताया गया है। नवग्रहों से संबंधित परेशानियों और अशुभ प्रभावों की शांति के लिए तुलसी पूजन तथा नियमित चालीसा पाठ को एक शुभ आध्यात्मिक उपाय माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी माता की आराधना से घर में सात्विकता बढ़ती है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। जिन लोगों को कार्यों में लगातार बाधाओं, पारिवारिक तनाव या मानसिक बेचैनी का सामना करना पड़ता है, वे श्रद्धापूर्वक तुलसी चालीसा का पाठ करते हैं। धार्मिक विश्वास के अनुसार इससे मनोबल मजबूत होता है और विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने की शक्ति मिलती है। हालांकि नवग्रह शांति से जुड़े इन परिणामों को धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यता के रूप में ही समझना चाहिए।

तुलसी चालीसा के नियमित पाठ का एक लाभ यह भी माना जाता है कि इससे व्यक्ति की दिनचर्या में अनुशासन आता है। सुबह उठकर स्नान करना, पूजा स्थल की सफाई करना, दीपक जलाना और कुछ समय भगवान के ध्यान में लगाना मन को शांत करने वाला अभ्यास हो सकता है।

मालिक जयेश जग्शी गाला हेतु प्रकाशक, मुद्रक **अश्विनी कुमार दुबे** द्वारा मोदी प्रिंटर्स, 24 बोमनजी लेन, फोर्ट, मुंबई-400001 (महाराष्ट्र) से मुद्रित कर महाराष्ट्र ग्रेन स्टोर्स, 28, डॉ. भगवानदास इंद्रजीत रोड, वालकेश्वर, मलबार हिल, मुंबई-400006 से प्रकाशित किया।
संपादकः **अश्विनी कुमार दुबे** (पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी है, न्याय क्षेत्र मुंबई), सहसंपादकः सुजीत मिश्रा ('दै.'राष्ट्रीय स्वाभिमान 'में सभी लोग सहयोगात्मक और अवैतनिक तौर पर कार्यरत हैं)
● **आर.एन.आई.:MAHHIN/2008/24084** ● ईमेलः rastriyaswabhiman@gmail.com ● भ्रमणध्वनि क्र. +919224733113

लोकतांत्रिक सशक्तिकरण की दिशा में पहल, काशी में भाजपा महानगर ने शुरु किया मतदाता जोड़ो अभियान-2026

वाराणसी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिकाधिक नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने और मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी महानगर वाराणसी ने 17 नवंबर से 'मतदाता जोड़ो अभियान-2026' की शुरुआत की। गुलाब बाग स्थित महानगर कार्यालय में महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में अभियान की रणनीति और आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई।

कार्यशाला का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित करने तथा वंदे मातरम् के सामूहिक गान के साथ हुआ।

ऑनलाइन फॉर्म-6 से पंजीकरण पर जोर

कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला एवं महानगर प्रभारी तथा विधान परिषद सदस्य अरुण पाठक ने विधानसभा



स्तरीय बैठकों और मतदाता पुनरीक्षण अभियान की कार्ययोजना साझा की। उन्होंने कहा कि ऑफलाइन प्रक्रिया में बीएलए-2, मंडल, जिला और निर्वाचन कार्यालय सहित कई स्तरों से गुजरना पड़ता है, जिससे फॉर्म स्वीकृति की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसे अधिक सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म-6 के उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी।

उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अगले दो दिनों में स्वयं एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन फॉर्म-6 भरकर पंजीकरण प्रक्रिया का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करें। साथ ही बी, सी और डी श्रेणी के आवंटित बूथों पर अगले 10 दिनों में 200 से 250 परिवारों से संपर्क कर 30 से 40 नए मतदाता जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। स्थानीय निकाय और विधानसभा मतदाता सूचियों के अंतर को कम करने तथा दोहरे नामों में सुधार के लिए ECINET और निर्वाचन आयोग के पोर्टल का उपयोग करने पर भी जोर दिया गया।

16 दिसंबर तक चलेगा अभियान

महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में बताया कि यह अभियान 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलेगा। इसके तहत 19 और 20 नवंबर को विधानसभा स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। वहीं 21-22 और 28-29 नवंबर को निर्वाचन आयोग के विशेष पुनरीक्षण अभियान में बीएलओ को सहयोग देने तथा बीएलए-2 की सूची जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

22, 23 और 24 नवंबर को सभी बूथों पर पदाधिकारियों की मौजूदगी में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद 28, 29 और 30 नवंबर को महिला मोर्चा के संयोजन में विशेष महिला मतदाता जोड़ो अभियान आयोजित होगा। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा बहुओं, बीसी सखियों और स्वयं सहायता समूहों का सहयोग लिया जाएगा।

बूथ स्तर पर होगी दैनिक समीक्षा

अभियान को प्रभावी बनाने के लिए आईटी विभाग द्वारा शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर दैनिक समीक्षा की व्यवस्था की गई है। मंडल प्रभारियों को आगामी तीन महीनों तक विस्तारक के रूप में कार्य करने का दायित्व दिया गया है। उन्हें प्रतिदिन सुबह 11 से 12 बजे तक शक्ति केंद्रों पर बैठक कर अभियान की प्रगति की समीक्षा करनी होगी।

कार्यक्रम का संचालन महानगर महामंत्री पूजा दीक्षित ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन अजय गुप्ता ने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर चंद्रशेखर उपाध्याय, राहुल सिंह, महानगर मीडिया संयोजक प्रमील पाण्डेय, अशोक जाटव, विकास बागी, प्रज्ञा पाण्डेय, प्रीति सिंह, अनुराग शर्मा, कुशाग्र श्रीवास्तव, सत्येंद्र सिंह, आत्माविश्वेश्वर, स्वास्तिक श्रीवास्तव, संदीप चौरसिया, नेहा कक्कड़, राजीव सिंह डब्बू, तारकेश्वर नाथ गुप्ता एवं बबलू सेठ सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यशाला का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

संशोधित वेतनमान की मांग पर न्यायिक कर्मचारियों की राज्यव्यापी हड़ताल, भिवंडी के 130 कर्मचारी भी शामिल

भिवंडी। अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान लागू करने की मांग को लेकर शुरू किए गए राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन काम बंद आंदोलन में भिवंडी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के 130 कर्मचारी भी शामिल हो गए हैं। मंगलवार को कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करते हुए न्यायालय परिसर के बाहर मूक प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के अधीक्षक जयवंत शिंगोले और दीवानी न्यायालय की सहायक अधीक्षक ज्योति भरत नांगरे ने किया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के अधीक्षक जयवंत शिंगोले ने बताया कि कर्मचारियों ने इससे पहले संवैधानिक तरीके से काली पट्टी बांधकर सरकार का ध्यान



अपनी मांगों की ओर आकर्षित किया था। इसके बावजूद सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने 31 जनवरी 2025 को संशोधित वेतनमान से संबंधित प्रस्ताव तत्काल मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास भेजा था, लेकिन अब तक इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार की लगातार अनदेखी के कारण कर्मचारियों को अनिश्चितकालीन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है।

राज्यव्यापी हड़ताल का असर भिवंडी के न्यायिक कामकाज पर भी पड़ा। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय तथा दीवानी न्यायालय में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध 1675 मामलों की कार्यवाही प्रभावित हुई। इसके चलते न्यायालय पहुंचे वादी और प्रतिवादियों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा।

शिक्षा से संवरेंगे गरीब बच्चों के सपने, अहीरौली में शुरू हुआ निःशुल्क शिक्षण केंद्र

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा और शिक्षण सामग्री

आर एस नेटवर्क। डॉ. उदय शंकर भगत

वाराणसी। आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से आयर बाजार के अहीरौली में सोमवार को श्री नित्य निकुंज रस सेवा संस्थान ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क शिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस पहल से क्षेत्र के गरीब बच्चों को बिना किसी आर्थिक बोझ के शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष आचार्य नित्यानन्द पाण्डेय ने कहा कि आर्थिक तंगी किसी भी बच्चे के भविष्य और शिक्षा की राह में बाधा नहीं बननी चाहिए। इसी सोच



के साथ निःशुल्क शिक्षण केंद्र की शुरुआत की गई है। यहां बच्चों को मुफ्त पढ़ाई के साथ आवश्यक शिक्षण सामग्री और शिक्षा किट उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जाएगा, ताकि वे बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।

कार्यक्रम के दौरान इस सामाजिक पहल में श्री विकास मिश्रा के विशेष योगदान की सराहना की गई। इस अवसर पर ग्राम प्रधान, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, ग्रामवासी, प्रधानाध्यापिका नेहा मिश्रा, संस्थान के पदाधिकारी एवं पत्रकार उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के अंत में आचार्य नित्यानन्द पाण्डेय ने समाजसेवियों और जागरूक नागरिकों से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद बच्चों को शिक्षित करना केवल किसी एक संस्था का नहीं, बल्कि पूरे समाज का दायित्व है। शिक्षा के माध्यम से ही बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उनके सपनों को साकार किया जा सकता है।

गोदाम में सेंधमारी कर 14.44 लाख का तांबा चुराने वाले पांच आरोपी गिरफ्तार

नारपोली पुलिस ने दो दिन में सुलझाई चोरी की गुत्थी, टेम्पो सहित 14.37 लाख रुपये का माल बरामद

भिवंडी। भिवंडी के गोदाम क्षेत्र में सेंधमारी कर तांबे का सामान चोरी करने वाले पांच आरोपियों को नारपोली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी का अधिकांश माल और वारदात में इस्तेमाल किया गया टेम्पो भी बरामद कर लिया है।

पुलिस के अनुसार, नारपोली पुलिस थाना क्षेत्र के राहनाल ग्राम पंचायत की सीमा में स्थित सद्गुरु कंपाउंड के एक गोदाम में 5 से 12 नवंबर के बीच चोरी हुई थी। अज्ञात चोरों ने गोदाम का शटर तोड़कर वहां रखा करीब 14 लाख 44 हजार रुपये कीमत का तांबे का सामान चुरा लिया था। इस संबंध में नारपोली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था।



वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय कादबाने और पुलिस निरीक्षक अतुल अडूरकर के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक महेंद्र पाटील, पुलिस उपनिरीक्षक आकाश पवार तथा अपराध प्रकटीकरण दल ने जांच शुरू की। टीम में पुलिसकर्मी चव्हाण, हुंडेकरी, गुंजाळ, भामरे, तडवी, सुरळकर, शिंदे, मथे, देसले और ताठे शामिल थे। तकनीकी विश्लेषण और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने महज दो दिनों में संदिग्धों का पता लगा लिया।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शौकत उर्फ वसीम अकबरअली खान (28), गयासुद्दीन सलाहुद्दीन चौधरी (21), सलमान शाबान अली खान (33), अंबिया सजाउद्दीन मिर्झा (32), सभी निवासी कौसा, मुंब्रा, तथा अब्दुल हासिम वदुत खान (38), निवासी उल्हासनगर नंबर-5 को हिरासत में लिया।

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चोरी में शामिल होने की बात स्वीकार की। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किया गया टेम्पो और 14 लाख 37 हजार रुपये कीमत का चोरी का सामान बरामद किया है। मामले की आगे की जांच पुलिस उपनिरीक्षक आकाश पवार कर रहे हैं।

वाराणसी में छात्रा से छेड़खानी के आरोपी ऑटो चालक का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

बीएचयू परिसर से पकड़ा गया था आरोपी, मेडिकल परीक्षण के दौरान पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने का आरोप

आर एस नेटवर्क। डॉ. उदय शंकर भगत

वाराणसी। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में छात्रा से छेड़खानी के मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया, जब गिरफ्तार आरोपी ऑटो चालक पुलिस अभिरक्षा से भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाते समय पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन ली और भागने लगा। इसके बाद हुई पुलिस मुठभेड़ में उसके दाहिने पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार, पूरा मामला सोमवार देर शाम का है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की एक छात्रा सोमवार शाम करीब 7:30 बजे बीएचयू की लॉ फैकल्टी के पास से गुजर रही थी। इसी दौरान वहां



से गुजर रहे एक ऑटो चालक ने कथित तौर पर ऑटो की रफ्तार धीमी कर छात्रा के साथ अश्लील हरकत की और उसके निजी अंगों को छुआ। छात्रा के शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।

आरोपी की पहचान मैनूद्दीन के रूप में हुई है। छात्रा की शिकायत पर लंका पुलिस ने छेड़खानी के आरोप में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने अपना मूल पता पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का बताया, जबकि वह वर्तमान में मिर्जापुर जिले के अदलहाट थाना क्षेत्र के नारायणपुर में रह रहा था।

पुलिस के अनुसार, आवश्यक कार्रवाई के बाद आरोपी को फैटम दस्ते के साथ मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान अस्सी नाला के पास रविंद्रपुरी रोड पर उसने कथित तौर पर पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन ली और फैटम वाहन से उतरकर भागने लगा। पुलिस टीम ने उसका पीछा किया। पुलिस का दावा है कि भागने के दौरान आरोपी ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाई। इस कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा।

इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर तत्काल बीएचयू ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के बाद इलाके में पुलिस की सक्रियता बढ़ा दी गई है। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

इस घटना ने एक बार फिर सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज कर दी है।

सेवानिवृत्त न्यायिक कर्मचारियों के हक के लिए ठाणे में चेन हंगर स्ट्राइक, अमोल धनराज केंद्रे ने दिया समर्थन

ठाणे। सेवानिवृत्त न्यायिक कर्मचारियों के अधिकारों और लंबित वेतन संशोधन की मांग को लेकर ठाणे में सरकारी विश्रामगृह के सामने एक दिवसीय चेन हंगर स्ट्राइक का आयोजन किया गया। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन का लाभ दिया जाए।

प्रदर्शनकारियों के अनुसार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 31 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र सरकार को वेतन संशोधन का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन लगभग 20 महीने बीत जाने के बावजूद इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। कर्मचारियों ने सरकार से प्रस्ताव को तत्काल मंजूरी देने और संशोधित वेतनमान लागू करने की मांग की। आंदोलन में 60 से 70 वर्ष से अधिक आयु के कई वरिष्ठ सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बीमारी और शारीरिक



परेशानियों के बावजूद हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्यायपालिका की सेवा में समर्पित किया, उन्हें अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार से मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर जल्द न्याय देने की अपील की।

आंदोलन स्थल पर धड़ाकेबाज युवा प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के संस्थापक अध्यक्ष अमोल धनराज केंद्रे पहुंचे और उन्होंने सार्वजनिक रूप से आंदोलन को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्यायपालिका की लंबे समय तक सेवा करने वाले वरिष्ठ कर्मचारियों को अपने जायज अधिकारों के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री और जिले के पालकमंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप कर वेतन संशोधन प्रस्ताव को तत्काल मंजूरी दिलाने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। धड़ाकेबाज युवा प्रतिष्ठान इन वरिष्ठ कर्मचारियों के संघर्ष में उनके साथ खड़ा है।

इस अवसर पर सतीश शिरसाठ, बी.टी. शेलार, अलका पुराणिक, चित्रा कोलगांवकर, जयंत भामरे, सुरेश दाभेकर सहित सैकड़ों सेवानिवृत्त न्यायिक कर्मचारी उपस्थित रहे।

पर्पल फेयर-2026 में दिव्यांगजनों की प्रतिभा और आत्मनिर्भरता को मिला मंच

दिव्यांगजनों द्वारा निर्मित चित्रकारी एवं हस्तशिल्प की प्रदर्शनी बनी आकर्षण का केंद्र

आर एस नेटवर्क। डॉ. उदय शंकर भगत

वाराणसी/जौनपुर। समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी), खुशीपुर वाराणसी द्वारा जिला प्रशासन जौनपुर के सहयोग से बीआरपी इंटर कॉलेज में पर्पल फेयर जौनपुर-2026 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विद्यासागर सोनकर उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य सलाहकार बोर्ड की सदस्य राधा सिंह, बीआरपी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. प्रमोद श्रीवास्तव तथा जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राजेश कुमार जायसवाल ने सहभागिता की।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों की प्रतिभा, कौशल और क्षमताओं को समाज के सामने प्रस्तुत करना तथा उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराने के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। सीआरसी वाराणसी के निदेशक आशीष कुमार झा ने अतिथियों का



स्वागत किया और केंद्र की ओर से दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण एवं पुनर्वास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।

आयोजन के दौरान दिव्यांगजनों द्वारा तैयार की गई आकर्षक चित्रकारी और हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। दिव्यांग उद्यमियों को अपने उत्पादों की बिक्री एवं प्रचार-प्रसार के लिए निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराए गए, जिससे उन्हें स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रोत्साहन मिला।

कार्यक्रम में टॉक शो, मोटिवेशनल स्पीच, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, सहायक उपकरण वितरण, यूडीआईडी एवं निरामया हेल्पडेस्क के साथ फूड एवं फन जोन जैसी विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित की गईं। इन गतिविधियों के माध्यम से दिव्यांगजनों को सरकारी सुविधाओं, योजनाओं और उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी गई।

पर्पल फेयर-2026 ने यह संदेश दिया कि दिव्यांगता किसी व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता की सीमा तय नहीं करती। यदि उन्हें उचित अवसर, संसाधन और प्रोत्साहन मिले तो वे न केवल आत्मनिर्भर बन सकते हैं, बल्कि समाज और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

ठाणे के कुछ इलाकों में 24 घंटे नहीं रहेगा पानी

ठाणे। मनपा क्षेत्र के अंतर्गत मुंब्रा, दिवा, कलवा वार्ड कमेटियों में महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से पानी सप्लाई किया जाता है। इस साल मॉनसून के बाद कम बारिश और एल नीनो के असर और अक्टूबर 2026 से मॉनसून के जल्दी जाने की वजह से, सरकार के फैसले के मुताबिक पानी में 10 परसेंट की कमी करने का फैसला किया गया है। इसके मुताबिक, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जांभूल वॉटर प्यूरिफिकेशन सेंटर से पानी की सप्लाई गुरुवार, 19/11/2026 को दोपहर 12.00 बजे से शुक्रवार, 20/11/2026 को दोपहर 12.00 बजे तक कुल 24 घंटे के लिए बंद रहेगी। इस बंद के दौरान, ठाणे मनपा के तहत दिवा, मुंब्रा (वार्ड नंबर 26 और 31 के कुछ हिस्सों को छोड़कर) और कलवा वार्ड कमेटियों के सभी इलाकों में 24 घंटे के लिए पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद रहेगी। नागरिकों को कृपया ध्यान देना चाहिए कि पानी की सप्लाई फिर से शुरू होने के बाद अगले 1 से 2 दिनों तक पानी का प्रेशर कम रहेगा। ठाणे मनपा ने नागरिकों से अपील की है कि वे पानी कटौती के समय पानी का कम इस्तेमाल करके ठाणे म का सहयोग करें।

भिवंडी में 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह, 9 दिसंबर को आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री करेंगे कन्यादान



भिवंडी। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम की सामूहिक कन्या विवाह की परंपरा अब महाराष्ट्र में भी शुरू होने जा रही है। इसी क्रम में भिवंडी स्थित श्री बागेश्वर धाम सनातन मठ में 7 से 10 दिसंबर 2026 तक 51 कन्याओं के सामूहिक विवाह महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव का मुख्य समारोह 9 दिसंबर को होगा, जिसमें आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की उपस्थिति में 51 कन्याओं का विवाह और कन्यादान संपन्न कराया जाएगा।

बागेश्वर धाम में वर्ष 2020 से जरूरतमंद और अनाथ कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। इसी सेवाभावी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2026 में महाराष्ट्र के भिवंडी में 51 कन्याओं के विवाह का संकल्प लिया गया है। आयोजकों के अनुसार, महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से पात्र कन्याओं का निर्धारित प्रक्रिया के तहत चयन किया जाएगा। चार दिवसीय विवाह महोत्सव के दौरान 7 से 10 दिसंबर तक विभिन्न धार्मिक और वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। आयोजन को सफल बनाने के लिए श्री बागेश्वर धाम सनातन मठ का व्यवस्थापक मंडल, पदाधिकारी और सेवादार तैयारियों में जुट गए हैं। आयोजकों का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक संपन्न कराना तथा समाज में सेवा, सहयोग और मानवता की भावना को मजबूत करना इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य है। महोत्सव में महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से श्रद्धालुओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सेवाभावी नागरिकों के शामिल होने की उम्मीद है। आयोजक मंडल ने समाज के सभी वर्गों से इस सामाजिक एवं सेवाभावी आयोजन में सहयोग करने की अपील की है।

भिवंडी में मरम्मत कार्य के कारण बुधवार को २४ घंटे पानी बंद

भिवंडी। राज्य में सूखे के कारण पूरे प्रदेश में जल संकट के बा द ल मंडरा रहे हैं, जिसके चल ते शहरी क्षेत्रों में सप्ताह में एक बार १८ घंटे की पानी क टौती शुरू हो गई है। इसी के तहत भिवंडी शहर में हर सोमवार को पानी बंद रहने के साथ-साथ अब बुधवार, १८ नवंबर को भी २४ घंटे के लिए जलापूर्ति बंद रहेगी। यह जानकारी महानगरपालिका के जलापूर्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता संदीप पटनावर ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है। भिवंडी मनपा क्षेत्र को पानी की आपूर्ति करने वाली तानसा पा इपलाइन पर व हाळदेवी मंदिर के पास ३०० मि.मी. व्यास का नया वॉल्व लगाने, गौतम कंपाउंड स्थित तानसा लाइन के एयर वॉल्व की मरम्मत, तानसा मुख्य पाइपलाइन के रिसाव की मरम्मत और धोबीतालाब टंकी के लिए नया वॉल्व लगाने जैसे अ त्यावश्यक रखरखाव और मरम्मत कार्य किए जाने हैं। इस कारण बुधवार १८ नवंबर की सुबह ९ बजे से गुरुवार १९ नवंबर की सुबह ९ बजे तक (कुल २४ घंटे) पानी की आपूर्ति बंद रहेगी, और इसके अगले एक दिन तक कम दबाव व कम मात्रा में पानी मिलेगा।

इस पानी कटौती के कारण श हर के मानसरोवर, खड़ी मशीन रोड, व हाळदेवी नगर, पद्मानगर, गायत्रीनगर, रामनगर, नवजीवन कॉलोनी, बी.एन.एन. कॉ लेज रोड, पटेल कंपाउंड ग ली नं. १, २, ३, भैयासाहेब आंबेडकर नगर, न्यू प्रकाशनगर, माधवनगर, सोमानगर, विठ्ठलनगर, गंगाराम वाड़ी, न्यू टावरे कंपाउंड, दूधबावड़ी, हाफिज नगर, आलमगीर वीडियो परिसर, न्यू इस्लामाबाद, आजमीनगर, खालीकशेठ चाल, दिवानशाह, हांडी कंपाउंड, समरूबाग, ईदगाह रोड सहित अधिकांश इलाकों में जलापूर्ति नहीं हो पाएगी। अतः जलापूर्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता संदीप पटनावर ने नागरिकों से इस बात पर ध्यान देने, पानी का संभलकर उपयोग करने और मनपा को सहयोग देने की अपील की है।

हिन्दी दैनिक
राष्ट्रीय स्वाभिमान

राष्ट्रीय स्वाभिमान
पत्र व्यवहार:रफ्तार इंडिया एक्सप्रेस, 31/33 पहला महला, पत्रावाला बिल्डिंग, वजु कोटक मार्ग लिंक शहीद भगतसिंह रोड, फोर्ट, मुंबई 400001, भ्र.ध्व. क्र.:9224733113
ईमेल:rastriyaswabhimaan@gmail com

04 मुंबई, बुधवार, 18 नवम्बर 2026 महाराष्ट्र

epaper.rashtriyaswabhimaan.in
www.rashtriyaswabhimaan.com

भिवंडी में मनपा के सार्वजनिक सभागृह पर निजी व्यक्ति का क जा, आयुक्त की औचक जांच में खुलासा

आयुक्त अनमोल सागर ने सभागृह की चाबी कब्जे में ली, संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश

भिवंडी। भिवंडी महानगरपालिका की संपत्तियों के रखरखाव और उनके उपयोग को लेकर मिल रही शिकायतों के बीच मनपा आयुक्त अनमोल सागर ने मंगलवार को शहर के विभिन्न स्थानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सहयोग नगर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और भादवड़ के सोनादेवी सभागृह का दौरा किया गया। निरीक्षण के दौरान



वार्ड क्रमांक 14 में सहयोग नगर स्वास्थ्य केंद्र के बगल स्थित देविदास गुलवी सभागृह पर एक निजी व्यक्ति का कब्जा होने का मामला सामने आया।

आयुक्त अनमोल सागर ने पाया कि महानगरपालिका के स्वामित्व वाले इस सार्वजनिक सभागृह की चाबी अनिलकुमार सुभाषचंद्र गुप्ता नामक व्यक्ति के पास थी। प्रशासन के अनुसार, संबंधित व्यक्ति लंबे समय से मनपा की संपत्ति का कथित तौर पर अनधिकृत उपयोग कर रहा था। इससे महानगरपालिका के राजस्व को नुकसान पहुंचने की आशंका भी जताई गई है।

मामले की जानकारी मिलते ही आयुक्त ने तत्काल सभागृह की चाबी अपने कब्जे में ले ली और संबंधित पुलिस थाने में अनिलकुमार गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज कराने के निर्देश दिए।

सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करना मनपा की जिम्मेदारी : आयुक्त

आयुक्त अनमोल सागर ने कहा कि महानगरपालिका की सभी संपत्तियों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है और संबंधित विभागों से उनकी विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है।

दिवा में नाइजीरियाई दंपति के घर से 10.63 करोड़ की ड्रग्स जब्त, मुंब्रा पुलिस की बड़ी कार्रवाई

2 किलो से अधिक कोकीन और मेफेड्रोन बरामद, पति-पत्नी गिरफ्तार; तस्करी के नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस



आर एस नेटवर्क। दिनेश चंद्र रावल

ठाणे। नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुंब्रा पुलिस के एंटी-नारकोटिक्स दस्ते ने दिवा के बेतवाडे गांव स्थित मैराथन नेक्स्टवर्ल्ड सोसाइटी में छापेमारी कर एक नाइजीरियाई दंपति के घर से 10 करोड़ 63 लाख 27 हजार 600 रुपये मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। पुलिस ने घर से 2 किलो 98.5 ग्राम कोकीन और 104.7 ग्राम मेफेड्रोन (एमडी) बरामद की है। इस मामले में नाइजीरियाई नागरिक चुकवुमेका इमैनुअल न्वाक्वो (41) और उसकी पत्नी यूकेरिया चुकवुमेका ओबियानुजू (41) के खिलाफ मुंब्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है।

पुलिस के अनुसार, मुंब्रा पुलिस स्टेशन के अमलदार नवनाथ थोर्वे को गोपनीय सूचना मिली थी कि बेतवाडे स्थित एक सोसाइटी में विदेशी नागरिकों द्वारा नशीले पदार्थों की बिक्री की जा रही है। सूचना के आधार पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गणेश जावदवाड के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन धागे के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस ने शुक्रवार, 13 नवंबर को मैराथन नेक्स्टवर्ल्ड सोसाइटी की ऑरा बिल्डिंग की 36वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट नंबर 3602 में छापा मारा।

पुलिस ने पंचों और फोरेंसिक टीम की मौजूदगी में फ्लैट की तलाशी ली। इस दौरान फ्रिज पर रखे प्लास्टिक के डिब्बे में सफेद पाउडर से भरी कई थैलियां मिलीं। जांच में इनके कोकीन और मेफेड्रोन होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने नशीले पदार्थों के अलावा एक खाली प्लास्टिक पाउच, इलेक्ट्रॉनिक तराजू, दंपति के दो मोबाइल फोन, पासपोर्ट और 7,600 रुपये नकद भी जब्त किए। जब्त की गई सभी वस्तुओं का कुल मूल्य 10.63 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है।

गौरतलब है कि इससे पहले मुंब्रा पुलिस के एंटी-नारकोटिक्स दस्ते ने एक अन्य कार्रवाई में करीब 1.5 करोड़ रुपये मूल्य के मेफेड्रोन के साथ तीन तंजानियाई और एक नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई के बाद दिवा में हुई करोड़ों रुपये की बरामदगी ने क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

पुलिस अब इस मामले में नशीले पदार्थों के आपूर्तिकर्ताओं, स्थानीय वितरकों और संभावित ग्राहकों के नेटवर्क की जांच कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि गिरफ्तार दंपति का अन्य ड्रग तस्करों से कोई संबंध है या नहीं। दिवा क्षेत्र में इतनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की बरामदगी को अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक माना जा रहा है।

पालघर को मिलेगी स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना को मंजूरी

विधायक स्नेहा दुबे पंडित के प्रयासों के बाद राज्य मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण निर्णय, मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय भी होगा स्थापित

आर एस नेटवर्क। प्रेम चौबे

पालघर। पालघर जिले की न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल ने पालघर में प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायालय तथा मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही सरकारी वकील कार्यालयों और उनसे संबंधित आवश्यक पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई है। इस निर्णय से पालघर को स्वतंत्र न्यायिक प्रशासन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस मांग को लेकर विधायक स्नेहा दुबे पंडित लगातार शासन स्तर पर प्रयास कर रही थीं।



गौरतलब है कि 1 अगस्त 2014 को पालघर ठाणे जिले से अलग होकर स्वतंत्र जिला बना था। हालांकि, जिला बनने के बावजूद न्यायिक कामकाज के लिए इसे ठाणे जिला एवं सत्र न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रखा गया था। इसके कारण जिले की न्यायिक व्यवस्था ठाणे के प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियंत्रण में संचालित होती थी। वर्तमान में वसई, पालघर और जव्हार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालयों के साथ वरिष्ठ एवं कनिष्ठ स्तर के दिवाणी न्यायालय कार्यरत हैं, लेकिन स्वतंत्र प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश का पद उपलब्ध नहीं था। इसके चलते महत्वपूर्ण अपीलों, बड़े मुकदमों और न्यायिक प्रशासन से जुड़े कई कार्यों के लिए पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं को ठाणे जाना पड़ता था।

विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने पालघर के लिए स्वतंत्र न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता लगातार शासन के समक्ष उठाई थी। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब जिले में न्यायिक कामकाज स्थानीय स्तर पर संचालित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इससे जव्हार, मोखाडा, डहाणू और तलासरी जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को न्यायिक कार्यों के लिए ठाणे तक लंबी यात्रा करने से राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही न्यायालयीन मामलों के निपटारे और प्रशासनिक समन्वय को भी गति मिलने की संभावना है।

इस निर्णय पर विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पालघर जिले की स्थापना के बाद स्वतंत्र प्रशासनिक व्यवस्था विकसित हुई है और अब सक्षम न्यायिक व्यवस्था की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उनका प्रयास है कि नागरिकों को न्याय पाने के लिए अनावश्यक यात्रा, समय और आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। जिले के सर्वांगीण विकास के साथ नागरिकों को सुलभ और सक्षम न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे।

ठाणे जिले में होगा मिनी ओलंपिक, 75 हजार से अधिक खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम

आर एस नेटवर्क। दिनेश चंद्र रावल

ठाणे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मार्गदर्शन में कल्याण लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे की पहल पर 'खासदार क्रीड़ासंग्राम सीजन-2' का आयोजन किया जा रहा है। डॉ. श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन की ओर से आयोजित यह खेल महोत्सव 20 से 29 नवंबर 2026 तक ठाणे जिले के कल्याण, ठाणे और भिवंडी तीन लोकसभा क्षेत्रों में आयोजित होगा। इसमें 75 हजार से अधिक खिलाड़ियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। 31 खेलों और 32 से अधिक खेल स्थलों पर आयोजित होने वाला यह आयोजन ठाणे जिले के मिनी ओलंपिक के रूप में देखा जा रहा है।



ठाणे स्थित हिंदू हृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे कलादालन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और स्थानीय प्रतिभाओं को बड़ा मंच उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों से मिले उत्साहजनक प्रतिसाद के बाद इस बार आयोजन का दायरा बढ़ाकर ठाणे और भिवंडी लोकसभा क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। भविष्य में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को अधिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे।

खेल महोत्सव का उद्घाटन शुक्रवार, 20 नवंबर को डोंबिवली स्थित संत सावलाराम महाराज क्रीड़ा संकुल में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की प्रमुख उपस्थिति में होगा। समापन समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। आयोजन के दौरान विभिन्न खेलों के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी प्रतिभागियों से मुलाकात कर उनका मार्गदर्शन करेंगे।

सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय खेल महोत्सव की संकल्पना से प्रेरित होकर सांसद क्रीड़ासंग्राम की शुरुआत की गई थी। इस वर्ष आयोजन को व्यापक स्वरूप देते हुए तीन लोकसभा क्षेत्रों के खिलाड़ियों को एक साझा मंच प्रदान किया जा रहा है। प्रतियोगिता का आयोजन सांसद नरेश म्हस्के, सांसद सुरेश म्हात्रे, जनप्रतिनिधियों, स्थानीय पदाधिकारियों और विभिन्न खेल संगठनों के सहयोग से किया जा रहा है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद नरेश म्हस्के, विधायक हेमंत पाटिल, राजेश मोरे, बालाजी किणीकर, रवींद्र फाटक, उपनेता राहुल शेवाले, प्रवक्ता शीतल म्हात्रे, युवा सेना के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्वेश सरनाईक, ठाणे की महापौर शर्मिला पिंपलोलकर, कल्याण-डोंबिवली की महापौर हर्षाली चौधरी, उल्हासनगर की महापौर अश्विनी निकम, जिला प्रमुख गोपाल लांडगे, पार्षद रमाकांत माढवी और युवा सेना के जिला अध्यक्ष जितेन पाटिल सहित विभिन्न खेल संगठनों के पदाधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

रिक्शा के किराए को लेकर हुए झगड़े में रिक्शा ड्राइवर की मौत, दो के खिलाफ केस दर्ज

ठाणे। रिक्शा के किराए को लेकर हुए झगड़े में 43 साल के रिक्शा ड्राइवर की मौत की घटना 15 नवंबर को सामने आई। पुलिस ने बताया कि इस मामले में कलवा पुलिस स्टेशन में दो रिक्शा ड्राइवरों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। मृतक बाबासाहेब रघुनाथ जनराव (43) अटिकोनेश्वर नगर, कलवा के रहने वाले थे और अकेले रहते थे। वह रिक्शा चलाने का काम करते थे। 15 नवंबर को उनका अपने रिक्शा मालिक दिनेश घाडी और उनके साथ आए एक व्यक्ति से रिक्शा के किराए को लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद तीनों घर से बाहर चले गए, ऐसा बाबासाहेब की साली सुनीता जनराव ने अपनी शिकायत में बताया है। घटना वाले दिन शाम करीब 7:15 बजे सुनीता को झाड़ी में घायल पड़े बाबासाहेब का वीडियो दिखा। वह अपने रिश्तेदारों के साथ मौके पर पहुंचीं। बाबासाहेब के सिर, हाथ और पैरों में चोटें थीं। उन्हें कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें एडमिट करने से पहले ही मृत घोषित कर दिया। इस बारे में सुनीता की शिकायत के आधार पर दिनेश घाडी और प्रेम राजपूत के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, और कलवा पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर प्रतापराव भोसले की देखरेख में आगे की जांच चल रही है।

ठाणे में 19 से 22 नवंबर तक सजेगी 27वीं महापौर कप राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रदर्शनी 'आविष्कार-2026'

देशभर के 692 फोटोग्राफरों की 7,018 तस्वीरों में से चयनित उत्कृष्ट छायाचित्र होंगे प्रदर्शित, विजेताओं का 22 नवंबर को होगा सम्मान

आर एस नेटवर्क। दिनेश चंद्र रावल

ठाणे। ठाणे महानगरपालिका और फोटो सर्कल सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 27वीं ठाणे महापौर कप राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता के चयनित छायाचित्रों की प्रदर्शनी 'आविष्कार-2026' का आयोजन 19 से 22 नवंबर तक किया जाएगा। यह प्रदर्शनी हिंदू हृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे कलादालन, तीन हाथ नाका, परबवाड़ी में आयोजित होगी।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मार्गदर्शन और महापौर शर्मिला पिंपलोलकर की अध्यक्षता में 19 नवंबर को शाम 5:30 बजे प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा। इस अवसर पर वरिष्ठ वन्यजीव फोटोग्राफर पद्म भूषण डॉ. रमाकांत पांडा प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

महापौर शर्मिला पिंपलोलकर ने हाल ही में प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए। इस वर्ष देशभर के 692 फोटोग्राफरों ने कुल 7,018 तस्वीरें प्रतियोगिता के लिए भेजीं। प्रतियोगिता का उद्देश्य फोटोग्राफी कला को प्रोत्साहन देना, देशभर के छायाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराना और

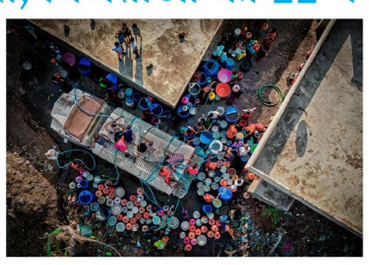

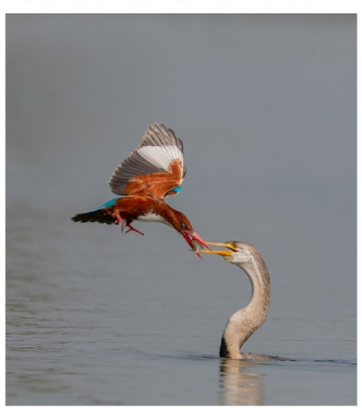

तस्वीरों के माध्यम से विभिन्न विषयों की कलात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना है।

प्रतियोगिता की विभिन्न श्रेणियों में स्ट्रीट फोटोग्राफी में कोलकाता के किशोर दास, प्रकृति एवं वन्यजीवन में भायंदर के डॉ. पराग नलावडे, लैंडस्केप एवं वाटरस्केप में कोलकाता के शिबाशीष शाह, उत्सव श्रेणी में हैदराबाद के उदय शंकर पाल तथा क्रिएटिव कलर्स श्रेणी में कोलकाता के राजेश धर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

प्रतियोगिता के लिए प्राप्त 7,018 तस्वीरों में से निर्णायक मंडल द्वारा चयनित लगभग 300 से 350 उत्कृष्ट छायाचित्र प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए जाएंगे। इनमें प्रकृति, सामाजिक जीवन, मानवीय संवेदनाएं, संस्कृति, रोजमर्रा की जिंदगी के अनूठे पल और विविध विषयों को कैमरे के माध्यम से कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। देशभर के फोटोग्राफरों द्वारा अपने कैमरों में कैद किए गए विशेष क्षण और उनके पीछे की रचनात्मक सोच प्रदर्शनी का प्रमुख आकर्षण होंगे। प्रतियोगिता के विजेता फोटोग्राफरों का सम्मान समारोह 22 नवंबर को शाम 6 बजे आयोजित किया जाएगा।

महापौर शर्मिला पिंपलोलकर ने ठाणे के नागरिकों, कला प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीनों से प्रदर्शनी में पहुंचकर देशभर के प्रतिभाशाली छायाकारों की कला का आनंद लेने की अपील की है।

मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन गंदगी में नंबर वन!

DRM और सीनियर DCM की नाक के नीचे फुट ओवरब्रिज बना कूड़ाघर

आर एस नेटवर्क। सुजीत मिश्र

मुंबई:पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता व्यवस्था की ऐसी तस्वीर सामने आई है जो रेलवे प्रशासन के तमाम स्वच्छता दावों को आईना दिखाने के लिए काफी है। स्टेशन के फुट ओवरब्रिज पर जगह-जगह कचरा, इस्तेमाल की गई खाद्य प्लेटें, खाने के अवशेष और गंदगी फैली हुई है। तस्वीरें देखकर साफ सवाल उठता है कि आखिर यात्रियों को इस गंदगी से कब मुक्ति मिलेगी?

17 नवंबर 2026 को दोपहर 12:51 से 12:52 बजे के बीच ली गई तस्वीरें बताती हैं कि दिन के व्यस्त समय में भी फुट ओवरब्रिज की सफाई व्यवस्था कितनी लापरवाह नजर आ रही है। यात्रियों



के आने-जाने वाले रास्ते पर कूड़ा बिखरा है लेकिन सफाई व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं देती। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पश्चिम रेलवे का महत्वपूर्ण स्टेशन है। इसके बावजूद फुट ओवरब्रिज की यह हालत रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है विशेषकर DRM और सीनियर DCM के लिए।

रेलवे प्रशासन स्वच्छता अभियान और यात्री सुविधाओं के बड़े-बड़े दावे करता है लेकिन जमीनी हकीकत इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। आखिर सफाई ठेकेदार किस बात का भुगतान ले रहा है? क्या संबंधित अधिकारियों ने कभी अचानक निरीक्षण करने की जहमत उठाई है?

फुट ओवरब्रिज की नियमित सफाई आखिर कौन करवा रहा है?

सफाई ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही?

सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी की निगरानी कौन कर रहा है?

क्या DRM और सीनियर DCM इस बदहाल व्यवस्था का स्वयं निरीक्षण करेंगे?

अब सवाल केवल गंदगी का नहीं,अधिकारियों की जवाबदेही का है।

मुंबई सेंट्रल जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन पर यदि यात्रियों को साफ-सुथरा फुट ओवरब्रिज नहीं मिल सकता तो रेलवे के स्वच्छता अभियानों का क्या औचित्य है?

रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को एसी कार्यालयों से बाहर निकलकर जमीनी हकीकत देखनी चाहिए। यात्रियों को भाषण और विज्ञापन नहीं, साफ-सुथरा स्टेशन चाहिए।

क्या पश्चिम रेलवे प्रशासन इस तस्वीर पर कार्रवाई करेगा या यह गंदगी भी अधिकारियों की नजरों से ओझल रहेगी?

महिला पुलिस कर्मी से छेड़छाड़ करने वाले निलंबित पुलिसकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज

भिवंडी। भिवंडी शहर में कार्यरत एक महिला पुलिस कर्मी का पीछा करने और अश्लील शब्दों का प्रयोग कर छेड़छाड़ करने के आरोप में एक निलंबित पुलिस सिपाही के खिलाफ शांतिनगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। जिस निलंबित पुलिस सिपाही के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, उसका नाम अंकुश रमेश सानप है।

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला पुलिस कर्मी जब शांतिनगर पुलिस थाने में कार्यरत थीं, तब आरोपी निलंबित पुलिस कर्मी अंकुश सानप ने अप्रैल 2023 से 9 जून 2026 के बीच पुलिस थाना परिसर में आकर लगातार

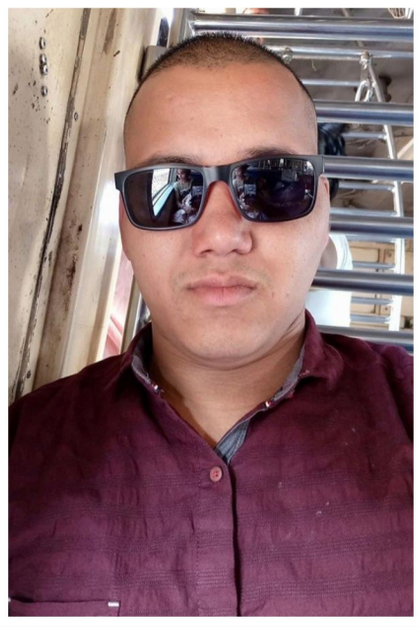

उनका पीछा किया, उनसे विवाद किया और अश्लील शब्दों का उपयोग करते हुए गाली-गलौज की। इसके अलावा, कई बार जब महिला पुलिस कर्मी घर जा रही थीं, तो उसने एसटी स्टैंड परिसर में भी उनका पीछा कर उन्हें परेशान करने की कोशिश की।

इस मामले में महिला पुलिस कर्मी ने विशाखा समिति के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। विशाखा समिति की रिपोर्ट के बाद पुलिस उपायुक्त डॉ. पवन बनसोड ने दोषी पाए गए पुलिस सिपाही अंकुश सानप के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज करने के आदेश दिए। इसके बाद शांतिनगर पुलिस थाने में पुलिस सिपाही अंकुश सानप के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75(3), 78, 79, 351(1)(5) और 352 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच पुलिस निरीक्षक दीपक बर्गे कर रहे हैं। एक महीने के भीतर भिवंडी में दो पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है।